G-695 राजमार्ग

चर्चा में क्यों ?

- चीन, 1957 में G-219 राजमार्ग के पूरा होने के 65 साल बाद, हिना तिब्बत को झिंजियांग से जोड़ने वाले अपने दूसरे प्रमुख राजमार्ग G-695 के निर्माण की योजना बना रहा है।
- नया राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य 2035 तक कुल 461,000 किमी (286,400 मील) राजमार्ग और मोटरवे का निर्माण करना है, ताकि इसकी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके और बुनियादी ढांचे के निवेश के माध्यम से उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दिया जा सके।

G-695 का संरेखण

- प्रस्तावित राजमार्ग के अनुमानित संरेखण के उल्लेख के अनुसार : झिंजियांग में माज़ा (काराकोरम दर्रे से 130 किमी. उत्तर-पश्चिम में) -ज़ांडा (हिमाचल/उत्तराखंड के विपरीत) -बुरंग (मानसरोवर के दक्षिण में और एलएसी पर लिपुलेख दर्रे से 16 किमी.) - ग्यरियोंग (नेपाल के सामने) - कम्बा (सिक्किम में नकु ला से 30 किमी. उत्तर में) - कोना (तवांग सेक्टर में एलएसी से 30 किमी. उत्तर में) - लुंज़े (कोना से 70 किमी. उत्तर पूर्व) से होकर यह मार्ग गुजरेगा।
- G-695 सीमा पर वास्तविक नियंत्रण (LAC) रेखा से 20-50 किमी. की औसत दूरी पर है। इसके विपरीत, G-219 इस दूरी से तीन से चार गुना अधिक दूर था। यह संभवतः इसके संरेखण के साथ सभी मौजूदा छोटी सड़कों को समाहित कर लेगा।

राजनीतिक निहितार्थ

- चीन के पास अपने सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रबंधन/विकास के माध्यम से अपनी संप्रभुता का दावा करने की एक स्पष्ट रणनीति है।
- "सीमावर्ती क्षेत्रों को नियंत्रित करना किसी देश पर शासन करने और तिब्बत को स्थिर करने की कुंजी है"। G-695 के नियमन को एक "भूमि सीमा कानून" के रूप में औपचारिक रूप दिया गया है, जो गैर-हान आबादी के कारण कब्जे वाले, विवादित या उग्रवाद के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों पर चीन की पकड़/दावों को मजबूत करने के लिए लागू किया गया है।
- 'शियाओकांग' (जिसका शाब्दिक अर्थ है 'अच्छी तरह से बंद') गांवों का निर्माण तिब्बत की सीमाओं के पास किया गया है। जिसके तहत चीनी उद्देश्य- आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देते हुए सीमा नियंत्रण/समेकन सुनिश्चित करना था।

सैन्य निहितार्थ

- मई, 2020 में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध शुरू होने के बाद से, चीन तेजी से अपनी सीमा अवसंरचना का विकास कर रहा है। कैप्टिव सौर ऊर्जा और लघु पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण LAC के निकट किया गया है, जो सर्दियों में निर्वाह क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है।
- G695 PLA के अंतर-क्षेत्रीय आंदोलन और रसद की सुविधा प्रदान करेगा। यह सीमा क्षेत्र के समग्र विकास के अलावा केंद्र में स्थित भंडार और रसद की भी अनुमति देगा।

भारत के लिए सबक

- बुनियादी ढांचे के विकास और बस्तियों द्वारा क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित करना।
- इनर लाइन परमिट की सुविधा को बढ़ाना।
- सीमावर्ती आबादी की सुरक्षा और विकास कार्यक्रम के लिए अपर्याप्त बजट के कारण विकास अवरूद्ध है।
- सरकार ने सीमावर्ती सड़कों के विकास पर काफी जोर दिया है, लेकिन पर्याप्त बजट, आधुनिक तकनीक और धीमी गति से निष्पादन की कमी के कारण प्रगति बहुत धीमी है। चीन ने 2,000 किलोमीटर से अधिक लंबे G-695 को विकसित करने के लिए 13 साल का लक्ष्य रखा है।
- वहीं दूसरी ओर लॉजिस्टिक लागतों के कारण रोहतांग दर्रे के विपरीत अटल सुरंग को विकसित करने में भारत को 20 वर्षों का समय लगा और अन्य 4 सुरंगों के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट की औपनिवेशिक प्रथा को समाप्त करे।

स्रोत –द प्रिंट

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स(FATF)

चर्चा में क्यों ?

- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा वर्ष के अंत तक अपेक्षित मूल्यांकन के चौथे दौर में भारत के आकलन के मद्देनजर सरकारी एजेंसियों ने धन शोधन रोधी और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण ढाँचे को मजबूत करने के प्रयासों में तेजी लायी गयी है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में -

- इसे फ्रांसीसी नाम, Groupe d'action financière (GAFI) के नाम से भी जाना जाता है।
- मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियों को विकसित करने हेतु G-7 देशों द्वारा इसे शुरू किया गया।
- G-7 ,1989 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- **उद्देश्य-** मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने हेतु कानूनी,विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और मानक निर्धारित करना।
- FATF एक "नीति-निर्माण निकाय" है जो इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय, विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने के लिए काम करता है।
- 2000 से, FATF ने FATF ब्लैकलिस्ट (औपचारिक रूप से "कार्रवाई के लिए कॉल" कहा जाता है) और FATF ग्रेलिस्ट (औपचारिक रूप से "अन्य निगरानी वाले क्षेत्राधिकार" कहा जाता है) को बनाए रखा है। ब्लैकलिस्ट के द्वारा वित्तीय संस्थानों को संसाधनों और सेवाओं को सूचीबद्ध से दूर स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया गया है।

भारत का रुख-

- सरकार ने भारत में **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद काउंटर-टेररिज्म कमेटी** के विशेष सम्मेलन सहित आतंक के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर केंद्रित सम्मेलनों की एक श्रृंखला भी आयोजित की है; 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन, जहाँ भारत ने अपने मुख्यालय की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है।

भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA):

- इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति पर कब्ज़ा करना है जो भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बचने के उपाय खोजते हैं। ऐसी संपत्ति को केंद्र सरकार को सौंपा जाता है।

ब्लैकमनी कानून, 2015 -

- इसके तहत विदेश में काला धन छुपाने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। टैक्स चोरी करने वालों पर 300 प्रतिशत जुर्माना तथा\ विदेशी संपत्ति के बारे में रिटर्न दाखिल न करने या अधूरा रिटर्न दाखिल करने पर सात साल की जेल हो सकती है।
- **सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली** (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 हथियारों और संबंधित वितरण प्रणालियों के पारगमन, निर्माण और हस्तांतरण को गैरकानूनी घोषित करता है। सामूहिक विनाश के हथियारों में जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियार शामिल हैं।

स्त्रोत –द हिन्दू

दयानंद सरस्वती

चर्चा में क्यों?

- भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया गया।

दयानंद सरस्वती के बारे में:

- स्वामी दयानंद सरस्वती एक दार्शनिक, सामाजिक नेता और वैदिक धर्म के सुधार आंदोलन 'आर्य समाज' के संस्थापक थे।
- उन्होंने 7 अप्रैल, 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की जो 10 सिद्धांतों के साथ जो पूरी तरह से भगवान, आत्मा और प्रकृति पर आधारित है।
- इस संगठन ने भारतीयों की धार्मिक धारणाओं में भारी परिवर्तन किया।
- वह 1876 में स्वराज के लिए "इंडिया फॉर इंडियन" के रूप में आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे।
- उन्होंने 'सार्वभौमिकता' का प्रचार किया, न कि किसी जाति विशेष का।
- उन्होंने शिक्षा प्रणाली का पूर्ण कायापलट किया और उन्हें अक्सर आधुनिक भारत के दूरदर्शी लोगों में से एक माना जाता है।
- स्वामी दयानंद सरस्वती के सपने को साकार करने के लिए 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल अस्तित्व में आए।
- उनकी सबसे प्रभावशाली रचनाओं में से एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया।
- उनके अनुयायियों में श्री अरबिंदो और एस. राधाकृष्णन शामिल थे।

स्त्रोत-पीआईबी

प्रीपेड भुगतान साधन

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने G-20 देशों के सभी इनबाउंड यात्रियों और अनिवासी भारतीयों को चुनिंदा हवाई अड्डों पर उनके मर्चेंट भुगतान (P2M) के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) का उपयोग करने की अनुमति दी है।
- RBI के अनुसार, प्रीपेड भुगतान उपकरण (PPI) जारी करने के लिए अधिकृत बैंक और गैर-बैंकिंग संस्थान भारत आने वाले विदेशी नागरिकों और NRI को रुपया-मूल्यवर्ग पूर्ण-KYC,PPI जारी कर सकते हैं।

प्रीपेड भुगतान उपकरणों (PPI) के बारे में

- PPI ऐसे उपकरण हैं जो उपकरणों पर संग्रहीत मूल्य के लिए वित्तीय सेवाओं, प्रेषण सुविधाओं आदि सहित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं।
- उदाहरण: प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को स्मार्ट कार्ड, मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड, इंटरनेट अकाउंट, इंटरनेट वॉलेट, मोबाइल अकाउंट, मोबाइल वॉलेट, पेपर वाउचर और प्रीपेड राशि को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी इंस्ट्रूमेंट के रूप में जारी किया जा सकता है।
- PPI जो भारत में जारी किए जा सकते हैं उन्हें वर्गीकृत करता है।
- **क्लोज्ड सिस्टम PPIs**: ये PPI केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए एक इकाई द्वारा जारी किए जाते हैं और नकद निकासी की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसे उपकरणों के संचालन के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
- **सेमी-क्लोज्ड सिस्टम PPIs**: ये PPI बैंकों (RBI द्वारा अनुमोदित) और गैर-बैंकों (RBI द्वारा अधिकृत) द्वारा उन व्यापारिक स्थानों पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए जारी किए जाते हैं, जिनका भुगतान उपकरण के रूप में PPI को स्वीकार करने के लिए जारीकर्त्ता के साथ एक विशिष्ट अनुबंध होता है।
- **ओपन सिस्टम PPIs**: ये PPI केवल बैंकों (RBI द्वारा अनुमोदित) द्वारा जारी किए जाते हैं और किसी भी व्यापारी द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऐसे PPI के माध्यम से एटीएम / पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों / बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) पर नकद निकासी की भी अनुमति है।

स्त्रोत –इंडियन एक्सप्रेस

भाषिणी मिशन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार 20 से अधिक स्थानीय भारतीय भाषाओं में उपलब्ध UPI -123 Pay के माध्यम से डिजिटल भुगतान करने के लिए मिशन भाषिणी की क्षमताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के साथ एकीकृत किया गया है।

भाषिणी मिशन के बारे में:

- यह एक स्थानीय भाषा का अनुवाद मिशन है जिसका उद्देश्य उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच की बाधा को समाप्त करना है।
- भाषिणी मिशन का उद्देश्य भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना है।
- **उद्देश्य-** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराना ,जिसका उपयोग भारतीय MSME , स्टार्टअप और व्यक्तिगत इनोवेटर्स द्वारा किया जा सके।
- इससे डेवलपर्स को सभी भारतीयों को उनकी मूल भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में एक अलग 'भाषदान' सेक्शन भी है जो व्यक्तियों को कई क्राउडसोर्सिंग पहलों में योगदान करने की अनुमति देता है और यह संबंधित Android और iOS ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध है।

यूपीआई 123 पे क्या है?

- यह एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्शन के बिना यूपीआई लेनदेन करने की अनुमति देगी।
- इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा लॉन्च किया गया था।
- UPI 123Pay के माध्यम से लेन-देन IVR (इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस) आधारित भुगतान समाधान, मिस्ड कॉल, ध्वनि-आधारित तकनीक और भुगतान ऐप के माध्यम से किया जा सकता है।

स्रोत –टाइम्स ऑफ़ इंडिया

KAMANYEVADHIKARASTE MAA PHALESHU KADAACHANA THE STUDY An Institute for IAS